भय व आशा के साथ

हर्ष मंदर

कुछ वर्ष सामूहिक चेतना में उन वर्षों में हुई दुखान्तिकाओं की यादगार के रूप में स्थाई घर कर लेते हैं। कुछ जख्म स्थाई दाग छोड़ जाते हैं। 1947 जहां एक ओर खूनी विभाजन के लिए याद किया जाता है वहीं इसे साम्राज्यवादी शासन से भारत को मिली आजादी के रूप में भी याद किया जाता है; 1948 धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथों गांधी की हत्या के लिए; 1962 भारत की युद्ध में शर्मनाक हार के लिए; 1975 आपातकाल लागू करने के लिए व प्रजातांत्रिक ताकतों के दमन के लिए; 1984 इंदिरागांधी की हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम के लिए; 1992 बाबरी मस्जिद गिराने के लिए तथा 2002 गुजरात में राज्य समर्थित हिंसा के लिए।

अभी इसका अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या इसी प्रकार 2008 भी दक्षिण मुंबई के संभ्रान्त इलाकों में आतंकवादियों के हमले के फलस्वरूप हुई सामुदायिक पीड़ा के लिए याद किया जाएगा। पर इस साल की याद में कई वर्षों तक मशीन गनों की गोलियों की आवाज व फिदायीनियों पर फेंके गए ग्रेनेडो की आवाज गूंजती रहेगी, तथा बेकसूर लोगों की पागल दिमाग वाले लोगों द्वारा स्टेशन पर व होटल के

कमरों में की गई नृशंस हत्या के दृश्य कायम रहेंगे।

धुंधली परछाईयां

इससे पहले भी 2008 वर्ष एक उथल-पुथल व समस्याओं से घिरा वर्ष रहा है। इस वर्ष में हम निरंतर आतंक के भय के साये में जीये हैं। नफरत ने देश के कई हिस्सों में कई लोगों की जानें ली हैं, व्यस्त बाजारों में बमों के धमाके हुए हैं, एक दिन बंगलूर में तो दूसरे दिन जयपुर में किसी और दिन गुजरात में, दिल्ली में, आसाम में या महाराष्ट्र में। बम गुमनाम व्यक्तियों द्वारा रखे गए जो संदेहास्पद संगठनों से जुड़े थे। जिन्होंने न केवल सड़कों पर खून, क्षत-विक्षत शव व ध्वस्त वाहनों को पीछे छोड़ा बल्कि लोगों के मन में भय, गुस्सा व बेहद नफरत भी छोड़ गए।

नफरत का खेल दूसरी तरह से भी देश के कुछ हिस्सों में खेला गया। 2008 में इसका निशाना ईसाई समुदाय, चर्च, अनाथालय, अस्पताल तथा इसाईयों के घर थे। इन्हें जला दिया गया या ध्वस्त कर दिया गया। भीड़ द्वारा की गई हिंसा में नन्स व पादरियों पर आक्रमण हुए व लगभग 300 गांवों से ईसाई आबादी साफ कर दी गई। यह उड़ीसा में कई सप्ताहों तक बिना रोकटोक चलता रहा। राज्य सरकार अचेतन रूप से बजरंगदल जैसे आक्रामक संगठनों पर लगाम कसने में असफल रही। ईसाइयों के खिलाफ यह हिंसा देश के अन्य हिस्सों, खासकर कर्नाटक में एक महामारी की तरह फैल गई।

2002 के बाद इस वर्ष मुस्लिम समुदाय पर सर्वाधिक हिंसा हुई। सबसे खतरनाक आक्रमण आसाम में हुए, जहां बंगाली मुसलमान नफरत के शिकार होते हैं (जो एक सदी से वहां रह रहे हैं)। मैं उदलगिरी व दारांग गया जहां इन दंगा पीड़ितों के कैंप हैं, जो कि धार्मिक आधार पर लगाए गए हैं। इन कैंपों में बहुत अशांति नजर आई व लोगों में जातीय भावनाओं के कारण गुस्सा था। महाराष्ट्र के धूलिया शहर में आजादी के बाद की सबसे बड़ी खूनी हिंसा हुई। सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि जम्मू में आदिवासी गूजर मुसलमानों को निशाना बनाया गया व अमरनाथ भूमि विवाद से उठे आंदोलन में जाम के दौरान श्रीनगर से आने व जाने वाले ट्रक-ड्राइवरों पर हिंसा की गई। कश्मीर की आजादी की लड़ाई जब चरम पर थी उस समय भी आतंकवादी हिंसा में हिंदू पर्यटकों या बाशिंदों को निशाना नहीं बनाया गया था। यह अत्यंत दुख का विषय है कि अलग-अलग रंग के राजनेता एक धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल वाले क्षेत्र में सांप्रदायिक नफरत फैलाने में सफल रहे।

आशा की किरणें

और इन सबके बावजूद, जनसामान्य द्वारा इसके विरोध में किए गए प्रतिकार आशा की किरण के रूप में देखने को मिले। ये प्रतिकार उन लोगों द्वारा किया गया जो नफरत पर आधारित राजनीति से ऊब चुके थे। आसाम को छोड़कर अन्यत्र किसी भी आतंकवादी हमले के बाद सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैली। यह बहुत सुखद बात है कि जनसामान्य की भावनाओं में आतंकवादी हिंसा के लिए भारतीय मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं माना गया, यद्यपि आतंकी अपने आपको इस्लाम के वफादार कहते आए हैं। दिल्ली व राजस्थान के चुनावों में मध्यमवर्गीय भी बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने गए और नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया कि मतदाता उन पार्टियों से प्रभावित नहीं हुए जो मुंबई हमलों को सांप्रदायिक रंग देना चाहती थीं। भारतीय मुसलमानों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर धार्मिक उलेमाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से इस्लाम का उपयोग राजनीतिक हिंसा के लिए करने को पूरी तरह से गलत ठहराया। बकरईद के अवसर पर, नमाज के बाद मुसलमानों ने काली पट्टी बांध कर मुंबई हादसे के बारे में देश के दुखः में अपनी सहभागिता दिखाई। मुझे इस बात पर दुख हुआ कि उन्हें अपने दुख को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए विवश होना पड़ा, ऐसा अन्य समुदायों ने नहीं किया।

परंतु इससे यह संदेश गया कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट होकर खड़े हैं। (जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिप्त होने तथा संभवतः पाकिस्तानी सेना व गुप्तचर एजेंसियों के कुछ तबके के लिप्त होने के पर्याप्त सबूत सामने आए हैं।)

चिंता इस बात की है कि शायद इन आतंकवादियों को हमारे घर से भी सहायता मिल रही है। इस वर्ष स्थानीय सहयोग के कई दावे किए गए हैं। इससे पूर्व आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तानी या बंगलादेशी आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार मान लिया जाता था। सरकार ने यह स्वीकार किया कि इस वर्ष हुए आतंकवादी हमले स्थानीय आतंकवादी संगठनों जैसे इंडियन मुजाहिदीन द्वारा समर्थित थे। पर इस दावे को और अधिक सबूतों से सिद्ध करने की आवश्यकता है।

एक चौंकानेवाली बात इस वर्ष यह हुई कि कुछ विलम्ब से अधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया कि एक आतंकवादी की एक नई धारा उन स्थानीय लोगों द्वारा पोषित आतंकवाद के रूप में उभरी है, जो लोग हिंदू मतावलंबी होने का दावा करते हैं। इनमें हिंदू साध्वी व सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी भी शामिल हैं। मानवाधिकार समूह कई वर्षों से कहते रहे हैं कि मुस्लिम पूजा स्थलों पर किए गए सभी हमले इस्लामी आतंकवादी समूहों द्वारा ही नहीं किए गए हैं। अब सबूतों ने यह साफ कर दिया है कि हिंदुत्व से जुड़े संगठनों का एक जाल है जिसने दुश्मनों पर हमला कर उन्हें ही बदनाम करने की योजना क्रियान्वित की। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि हेमंत करकरे जिसने हिंदुत्व आतंकवादियों के विरुद्ध जांच की अगवाई की थी वे मुंबई हमले में इस्लामी आतंकवादियों से मुठभेड़ में मारे गए। हेमंत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में न केवल सार्वजनिक सेवा का बल्कि एक उत्कृष्ट नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके जाने से हमने बहुत कुछ खोया है।

विश्वसनीय प्रमाण

हिंदुत्व आतंक के प्रमाणों ने इस मिथक को दफन कर दिया है कि ''सभी आतंकी मुस्लिम होते हैं।'' हिंदुत्व संगठनों का पार्टीशन के दंगों से ही रोल नफरत फैलाने का रहा है, यह बात विदित थी, पर अब यह प्रमाणों से साबित है कि इन संगठनों के कुछ भाग व्यक्तिगत आतंक फैलाने का काम करते हैं। हिंदुत्व टिप्पणीकार एवं एल. के. आडवाणी जैसे नेता 'हिंदू आतंकवाद' कहने पर आपत्ति करते हैं। वे पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वे कहते हैं कि आतंकवाद के साथ किसी धर्म के नाम को जोड़ने से गलत रूप से उस धर्म को मानने वाले सभी लोगों पर लांछन लगता है। हर व्यक्ति बेकसूर होता है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध नहीं होता, लोकतांत्रिक तरीके से उसकी जांच हो हरेक को यह अधिकार है। यह सब बातें निर्विवाद हैं परंतु इसमें दुख इसी बात का है कि अब तक कई वर्षों तक जब मुसलमानों पर कलंक लगाया गया और उनकी लोकतांत्रिक सुरक्षा नकारी गई, आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर तब इनमें से किसी ने विरोध करना उचित नहीं समझा।

भारत के कई भागों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जाता रहा है।, उत्तर-पूर्व व उत्तर-पश्चिम में तथा कई घने जंगलों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बल बिना रोक-टोक के कार्य करते हैं और उन्हें धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की सुरक्षा मिली हुई है। मणिपुर की शर्मिला इन मूलभूत स्वतंत्रता से वंचितों की एक अच्छी मिसाल है जिसने सन् 2000 से खाना खाने से इन्कार कर दिया है, अपनी अहिंसात्मक लड़ाई के लिए। विनायक सेन एक डॉक्टर व मानवाधिकार कार्यकर्ता पूरे 2008 तक जेल में बंद रहे। उनके जल्द छूटने की बहुत कम आशा है। हर आतंकवादी हमले के बाद मुस्लिम युवकों को बंदी बनाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं व कई बार एनकाऊंटर में मार दिया जाता है।

यह वर्ष वैश्विक स्तर पर आर्थिक परेशानी का भी वर्ष रहा है। अमेरिका में बैंकिंग घपलों के कारण भारतीय शेयर बाजार धराशाही हो गए। इससे लाखों लोगों की बचत डूब गई। पर भारत के करोड़ों गरीबों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा जो बमुश्किल अपनी जिंदगी बसर करते हैं, रात को भूखे सोते हैं, जिन्हें मूलभूत स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, अधिकतर उन्हें काम नहीं मिलता, और वे बंधुवा बने रहते हैं, उन्हें बहुत दूर शहरों में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है ताकि वे अपने परिवारों को जीवित रख सकें। ऐसे लोग पहले भी इसी तरह का जीवन जी रहे थे और वैश्विक आर्थिक संकट के बाद भी वे ऐसा ही करते रहेंगे। उनके भाग्य में इससे और खराबी क्या आ सकती है।

अनसुना भारत

इस 60 से 80 करोड़ के दूसरे भारत के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं आयी। पर इनके लिए भी आशा की कुछ किरणें दिखाई देने लगी हैं। भारत एकमेव देश है जिसने 100 दिन के काम की गारंटी हर परिवार को दी है जिसे इसकी मांग है। इससे सबसे बुरे संकट से कुछ निजात मिली है, जिन राज्यों में यह योजना प्रारंभ हो गई है। सभी गरीब वृद्धों के लिए पेंशन की योजना लागू की गई है। बहुतों के लिए यही उनके जीवन का आधार है। करीब 14 करोड़ बच्चों को कोर्ट के आदेश से गरम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्यमवर्गीय सूचना के अधिकार द्वारा सरकार में अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।

अतः 2008 के वर्ष को किस रूप में याद किया जाएगा? इस वर्ष आतंकवादी हिंसा वैश्विक आर्थिक संकट ने भारत के धनाढ्य वर्ग की सुरक्षा में सेंध लगाई है, इस वर्ष नफरत की राजनीति ने अपनी सीमाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाई हैं। पर इस वर्ष सामान्य स्त्री-पुरुषों ने अपने आपसी विश्वास व उन सरकारों में भी विश्वास को दृढ़ता से कायम रखा जो सरकारें असफल रहीं। इन लोगों ने अपनी मानवता साहस व जूझने की क्षमता में भी विश्वास कायम रखा। यह एक और वर्ष था जब उन्हें किनारे तक धकेला गया फिर भी वे टिके रहे, एक बार फिर।
